

CF प्रहारागपर
21/11/14

2

1 काप्रदिम सागर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर, म.पु.

R- 3461- II/14

मोहन पिता जीवन पाल उम 35 वर्ष,

साकिन्-बोतराई, तहसील पथीरया, जिला दमोह, म.पु.

...पुनरीक्षणकर्ता

II बनाम II

2014 परजोत्तम पिता नन्हेलाल सेन, उम लगभग 40 वर्ष,

साकिन्-बोतराई, तहसील पथीरया, जिला दमोह, म.पु.

...उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.पु.भू.राजस्व संहिता :

पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पथीरया तहसील पथीरया जिला दमोह .म.पु. के राजस्व प्रकरण

क्रमांक-165बी/121/वर्ष 2013-2014 में उत्तरवादी द्वारा पेश धारा

32 म.पु.भू.रा.संहिता के तहत पेश अन्तारिम आवेदन स्वीकृत आदेश

दिनांक 22.07.2014 से दुखित होकर समयावधि के भीतर पेश किया है

पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हैं कि:- मौजा बोतराई प.ह.सं.3 तहसील

पथीरया जिला दमोह म.पु. में स्थित भूमि ख.सं.244, 245 के उत्तर-

वादी अनावेदक न तो भूमि स्वामी हैं और न ही मालिककाबिज हैं न

ही उपरोक्त भूमि उनकी पैत्रिक भूमि है वर्तमान में ख.सं. 244/1 रकवा

0.74 हे० राजस्व अभिलेख में महादेव हीरया, हीरराम पिता भाक्सींग

के नाम दर्ज है । ख.सं.244/2 रकवा 0.81 हे० भूमिराजस्व अभिलेख में

शालकराम, कालूराम, रामेश्वर, नरेश, गणेश, पिता काशीराम के नाम से दर्ज

है। ख.सं.245/1 रकवा 0.79 हे० राहुल वल्द देवराज के नाम से तथा

ख.सं.245/2 रकवा 0.40 हे० कल्पना पीत कामतापुसाद के नाम से

राजस्व रिकार्ड में बेनामा के आधार पर दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि पर

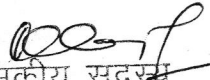
काप्रदिम सागर (म.पु.)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3461-एक/14

जिला ~~समर~~ दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि. आ हस्ताक्षर
06-01-15 सागर कैम्प	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री बलराम प्रजापति उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार तहसील व जिला दमोह के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 22-7-2014 का अवलोकन किया गया, जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>3- तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी दिनांक 22-7-14 को स्थगन आदेश जारी किया गया है, प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया है । आवेदक को अपनी साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर तहसील न्यायालय में उपलब्ध है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p>	


प्रशासकीय सदस्य